RAJYA SABHA

Wensday, the 15th December, 1993/ 24 Agrahayana, 1915 (Saka)

The House met at eleven of the clock, DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. 181,

stioner (Shri Viren J. Shah and pramod Mahajan) were absent. For ser, vide col.... Infra.]

RI S.S. AHLUWALIA: Madam, in suay's Question List, Question No. *wice printed. Question No. 182 is as 181.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is ... y corrected.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is not corrected. I think the Secretariat has hangcd the press people.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is Gvernment of India Press which prints "hey have issued an erata. It is being .plied. Anyhow, I would ask the lariat to tell the Press to be very ll about these things.

SH RIMATI JAYANTHI ARAJAN: It is also spelt wrongly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There and be more carefulness.

यों द्वारा श्रीनगर स्थित दूरदर्शन केन्द्र पर राकेटों से किया गया हमला

2. श्री राम नरेश यादव: क्या गृह मंत्री यह ी कृपा करेंगे कि:

ग्रवादियों ने श्रीनगर स्थित दूरदर्शन केन्द्र पर ि राकेटों से हमला किया है;

यदि हां, तो इस हमले से कितना नुकसान ौर

न-संचार प्रणाली के संरक्षणार्थ सरकार ने ए किये हैं?

राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): ी ए. तृ। 25.11.1993 को लगभग 2030 बजे उग्रवादियों ने श्रीनगर में दूरदर्शन केन्द्र परिसर की ओर एक राकेट फैंक था।

(ख) राकेट, दूरदर्शन केन्द्र के प्रशासनिक सह आवासीय ब्लाक से टकराया और इससे केन्द्र के स्टेशन इंजीनियर, श्री एस॰पी॰सिंह के आवासीय भवन के स्नानागार की छत को क्षति पहुंची, और उन्हें चोट लगी। श्री सिंह को तुरंत ही सेना अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

(ग) परिसर के आसपास के सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की गई है और उन्हें मजबूत बनाया गया है तथा चौकसी बढ़ा दी गई है।

श्री राम नरेश यादव: महोदया, जो मैंने प्रश्न किया था उसका जो उत्तर आया है वह बड़ा ही वेग लगता है। इसलिए कि अगर मंत्री जी मेरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो वह यह है— जन-संचार प्रणाली के संरक्षणार्थ सरकार ने क्या-क्या प्रबन्ध किये हैं? आपने उत्तर दिया है— परिसर के आसपास के सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की गई है और उन्हें मजबूत बनाया गया है तथा चौकसी बढ़ा दी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सेन्टर ऐसा है जिस पर इसके पहले भी तीन बार हमले हो चुके हैं। यह भी सदन को जानकारी है कि अभी कुछ समय पहले इसी दूरदर्शन के न्यूज रीडर श्री मोहम्द शफी की हत्या हुई थी। इसके पहले इसी दूरदर्शन के निदेशक श्री लासा कोल की भी हत्या हुई थी। इसके साथ सूचना विभाग, आल इंडिया रेडियो के अधिकारियों की भी वहां पर हत्या हुई। दूसरे जो सरकार के सूचना विभाग हैं वहां पर, उनके अधिकारियों की भी हत्या हुई। इसी तरह से हत्या का क्रम चला आ रहा है यह बहुत ही दुखद और चिन्तनीय है। इसलिए कि पाकिस्तान ने वहां पर कश्मीर में एक तरह से प्रोक्सी वार छेड़ दिया है उस कश्मीर में जिसे पाकिस्तान अपना कहता है। 125 वहां पर प्रशिक्षण केन्द्र हैं। पंजाब की सरहद पर वहां पर लगभग 25 केन्द्र हैं। 3000 किलोमीटर की हमारी जो सरहद है वह बहुत सेंसेटिव हो गई है। कश्मीर जो भारत का अविभाज्य अंग है उस पर बहुत ही खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हजरतबल का मामला सरकार ने बहुत बुद्धिमानी के साथ हल किया उसके बाद फिर घटनाओं का हो जाना सचमुच में कश्मीर में एक जबर्दस्त चुनौती है। कश्मीर के अंदर आतंकवाद को जिस तरह से पाकिस्तान पैदा कर रहा है वह भी हमारे लिए चुनौती है। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से

जानना चाहता हूं कौन कौन से निश्चित रूप से कदम आपने उठाये हैं जिससे वहां के अधिकारियों की रक्षा हो सके और संचार के माध्यम ठीक ढंग से चल सकें? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राजेश पायलट: मैडम, यह बात सही है कि दोनों केन्द्र आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन श्रीनगर से शिफ्ट कर दिये गये थे क्योंकि मिलिटेंट की इतनी ज्यादा कार्रवाई इन पर चल रही थी कि लोग घबरा गये थे। इस बारे में इन्फरमेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टरी से हम लोगों ने बातचीत की है इन कर्मचारियों की बहादुरी को देखकर जिन्होंने फिर यह जिम्मेदारी ली कि हम दुबारा दोनों केन्द्रों को चालू करेंगे। और जो हमारे साथी एस०पी० सिंह थे जिनकी इसमें मौत हुई है, ये उन कर्मचारियों में थे जिन्होंने बहुत हिम्मत से इनिसिएटिव लिया और यह पहले अफसर थे जिन्होंने श्रीनगर जा कर काम चालू किया। हमने सेक्यूरिटी का भी काफी इंतजाम कर रखा था। जितनी उस वक्त जरूरत थी जो कमेटी बैठी थी, उन्होंने जो जरूरी समझा वह किया गया था। लेकिन यह राकेट का एटैक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। उस वक्त वे खाना खाने के बाद बाथ रूम में हाथ धोने के लिए गये। खाना खाने के बाद एटैच्ड बाथ रूम में हाथ धो रहे थे तो बाथ रूम की बाहरी दीवार पर राकेट लगा जिससे इनको चोट आई और उनकी डेथ हो गई। यह बात राम नरेश जी की सही है कि यह बड़ा चेलेन्ज मिलिटेन्ट की तरफ से और पाक एडेड आर्गेनाइजेशन्स की तरफ से है। दोनों का केन्द्र हमेशा आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन रहा है। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे मिडियम, हमारे प्रचार मिडियम किसी भी तरह से वहां सफल हों। वे हमेशा चुनौती देते रहे हैं। वे चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का रेडियो और टेलीविजन हैं वही जम्मू कश्मीर के भाई देख सकें जिससे उनका प्रचार हमेशा हो और वे जो गलत अफवाह फैलाते हैं उसको हम काउन्टर न कर सकें और हम अपनी बात देश के इस हिस्से तक न पहुंचा सकें। यह चुनौती का काम है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी चाहे दूरदर्शन के हों या आल इंडिया रेडियो विभाग के हों, वे बहुत बहादुरी के साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सरकार की तरफ से और भी काम किये गये हैं। अभी पिछले हफ्ते में उन्होंने मीटिंग की है कि कोई ऐसी स्क्रीन वहां पर लगाई जाये जिससे कितनी दूरी पर भी वे हों वे इसको न देख पायें कि इस स्टेशन के अन्दर क्या हो रहा है। उसके बारे में भी उन्होंने पिछले हफ्ते में साइंटिस्ट लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और उसमें भी उन्होंने कदम उठाये हैं। राम नरेश जी की चिन्ता इस संबंध में सही है दुर्भाग्य यह है कि जब ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो मेहनत जो की हुई है वह भी बेकार लगने लगता है लेकिन सदन इस बात का विश्वास रखे कि कश्मीर का प्रशासन और सरकार मिलकर इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो रहे हैं उन पर पूरी तरफ से कोशिश क रहा है।

उपसभापति: उन्होंने बहुत विस्तार में जवा दिया है।

श्री राम नरेश यादव: महोदया, यह सचमु जिस प्रकार से श्री एस०पी० सिंह की हत्या हुई समझता हूं कि मैं ही नहीं पूरा सदन उनके साथ अ संवेदना व्यक्त करता है। उसके साथ साथ एक जरूरी है कि पाकिस्तान तीन तरह से काम कर र एक तो वह प्रशिक्षण दे करके कर रहा है और दूस नारकोटिक ड्रग्ज जो स्मगल होते हैं उसके आधार प पैसा पैदा होता है उससे हथियार खरीदे जाते हैं। तीस जो प्रचार और प्रसार के माध्यम हैं उसमें किताबों का प्रकाशन वहां से कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छा और मजबूत वहां पर जो कम्यूनिकेशन का सेंटर है उन्होंने लगा रखा है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेडियो लगा रख है। इस तरह से वहां पर स्थिति बन रही है। इस पू घाटी में जहां पर छः लाख पर्यटक करीब करीब आते वहां की आर्थिक स्थिति पूरे देश के पैमाने पर खराब रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब इस तरह हरकत कर रहा है तो उससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर क्या क्या कदम उठा रहे हैं? इसके साथ साथ सरहद पर जब मामला आता है, हथियार आते किताबें आती हैं, प्रचार सामग्री आती है जो रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? अपने प्र (ब) भाग में मैं यह जानना चाहता हूं कि राजनै प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आप क्या कर रहे पंजाब के मामले में किया गया तो मामला हल हो क्योंकि वहां पर लोकप्रिय सरकार आई तो उसने कदम उठाये और मामला हल हो गया। उसी कश्मीर का जो मामला है, जब तक आप र प्रक्रिया आरम्भ नहीं करेंगे तब तक कश्मीर क ऐसे ही बना रहेगा और खराब होता चला इसलिए राजनैतिक प्रक्रिया शुरु करने के लिए क्या कदम उठाये हैं, यह मैं जानना चाहत

श्री राजेश पायलट: मेडम, यह बात सह कश्मीर में संचार व्यवस्था इतनी बिगड़ गई

1991 में हमारा कोई टेलीफोन वहां पर नहीं था। श्रीनगर जैसी प्रोपर जगह पर भी टेलीफोन एक्सचेंज ठप कर दिया गया था और इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज वहां पर भेजा गया जो उस वक्त मैं कम्यूनिकेशन मिनिस्टर था, इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने के लिए मना कर दिया गया था और कोई भी कर्मचारी इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने के लिए तैयार नहीं था। जो हमारे टेलीफोन के छोटे छोटे एल०पी०टी० मंजूर किये गये थे वे भी वहां पर नहीं लगने दिये गये। हम शाम को काम करते थे तो उनको खत्म पाते थे। संचार व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी। लेकिन पिछले एक, सवा साल में संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पर एस०टी०डी० लग सकती थी वे लगी हैं। उसमें सुधार दीखा था, डेवलेपमेंट एक्टिविटीज भी शुरू हुई थी। मैं खुद वहां गया। जाकर मैंने कुछ अधिकारियों से बात की। हर ब्लाक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर्मचारियों को बिठाया और उनमें इंटरेस्ट पैदा किया था। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा मैंने सदन में कहा कि अगर एक इंसीडेंट जम्मू-कश्मीर में ऐसा हो जाता है, खासकर वेली में तो सारी दो-तीन महीने की मेहनत बराबर हो जाती है। सदन यह विश्वास रखे कि सरकार का मन है कि वहां पर जल्दी से जल्दी राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हो। पिछली बार जब वहां पर मीटिंग हुई तो हमाने सारे अपोजीशन पार्टीज के लीडर्स से बुलाया था।

डा० बापू कालदाते: किस आधार पर यह विश्वास रखें कि जल्दी से जल्दी होगा।

श्री राजेश पायलट: मैं बता रहा हूं। आधार उसका यह है कि जो पोलिटिकल पार्टियों के लीडर्स बुलाये थे, उस दिन उनसे बातचीत हुई थी और उसमें दो आप्शन हमारे सामने आये थे। एक तो यह था कि सदन और सरकार की तरफ से हमेशा होता रहा कि इसमें पोलिटिकल पार्टीज इनीसियेटिव लें। लेकिन वहां बंदूक का डर अभी भी इतना है, पूरी वैली में नहीं तो कम से कम वहां के कुछ पैकेट्स में इतना है कि बंदूक की डर की वजह से कोई भी आदमी बाहर निकलने से भी घबराता है। तो सरकार के सामने दो प्रश्न हैं। एक तो बंदूक का डर कम करना ताकि लोगों का भय खत्म हो जाय और उसके बाद वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हो। तो दो आप्शन अवेलेबल थे। इसके लिये हमने वहां पर पोलिटिकल एडवाइजरी सिस्टम लगाया कि जो स्टैटिंग कौंसिल हैं वह एडवाइजरी कौंसिल के रूप में काम करे और वह लोगों से मिलकर प्रशासन को बताये कि लोगों को यह तकलीफ है। ये दो बातें चली। इस बारे में पोलिटिकल पार्टीज से भी डिसकशन शुरू हुआ लेकिन इसी बीच हजरतबल इन्सीडेंट हो गया और फिर वह मामला पीछे पड़ गया। जैसा होम मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब राजनैतिक पार्टियों से बातचीत करके, इस बारे में एक राजनैतिक मन बनाकर, इस में जल्दी काम करें। मैं यादव जी की बात से सहमत हूं। मैं भी जब वहां दौरे पर जाता हूं तो लोग मिलते हैं और वे अपना दुख बताते हैं कि हम तो दो बंदूकों के बीच में बैठे हुए हैं। उनके मन में दहशत बैठी हुई है। इसलिये वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करने का सरकार का मन है और इसका उपाया सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इसकी शुरूआत की जाय। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक लोगों की बात प्रशासन तक नहीं पहुंचेगी, प्रशासन उनकी तकलीफों को दूर नहीं करेगा तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इन नीति के अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव: महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने यह पूछा था कि जो सरहदें हैं, उनसे जो आतंकवादी आते हैं उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं।

श्री राजेश पायलट: इन्फिलट्रेशन मिलिटेंट्स का जो राम नरेश यादव जी ने पूछा, मैडम यह बात सही है कि लोग आते रहे हैं। हमारा प्रयास रहा कि न आयें लेकिन आते रहे। लेकिन यह बात भी सही है कि कहीं कहीं से पहुंचे जरूर हैं और इनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन इतना इन्फिलट्रेशन नहीं हुआ। उन्होंने यहां नवयुवकों को ट्रेनिंग देकर, हमारे लोगों को हथियार दे देकर उनकी संख्या में वृद्धि की है और उनकी संख्या बढ़ी है। बहुत सख्ती बार्डर पर है और आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि कितनी किलिंग बार्डर पर की जा रही है। क्रासिंग पर लोग मारे गये हैं। पिछले एक-सवा साल में इनमें वृद्धि हुई है और इस वृद्धि की वजह यह है कि हमारे पैरा-मिलेटरी फोर्सेज और आर्मी ने बहुत सख्त तरीके से वहां पर चौकसी की है। फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी एन्ट्री हुई है। बहुत चौकसी के बाद इसको रोक पाये हैं। जहां तक कैंपों का सवाल है, सरकार ने सरकारी स्तर पर पाकिस्तान के साथ यह मामला उठाया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है, बंदूक चलाना सिखाकर, प्रशिक्षण देकर जो हमारी देश की सीमा में भेजा जाता है, इस बारे में हम लोगों ने कई बार उनसे चिंता जाहिर की है और पाकिस्तान से सख्त लफ्जों में कहा भी है कि भई पेशेंस की भी हद होती है। कहां तक हम लोग इस पेशेंस के साथ यह बर्दाश्त करते रहेंगे। यह बात भी उनको कनवे की गयी है। मुझे पूरी

उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत की जनता और भारत सरकार की भावनाओं को समझेगा। हम लोग पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं लेकिन अगर हम एक दूसरे से तंग होते रहेंगे तो यह बात बहुत खतरनाक हो सकती है।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, we are passing through a very unfrotunate phase in this country, and it is quite evident from the hon. Miniser's reply that the Government-bi it this Government or the previous Government, I am not at all on party lines—has failed to curb militancy and terrorism. A singal has been sent out that terrorism and militancy are being rewarded and the voice of sanity is being punished. Madam, it is very clear from the hon. Minister's reply कि बन्दूक का डर

अभी भी इतना खौफनाक है कि लोग बाहर जाने से कतराते हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं अपने घर से। Why do we require a Government? I would like to ask the hon. Minister. Why do we require a Government if people do not feel secure? These merchants of death have not spared even the places of worship, be it a gurudwara, be it a masjit, be it a mandir or a church. They have not spared any place, right from stock exchanges to places of worship. Whenever such things happen, we very conveniently say, that it is a foreign hand. You are a Government. You are a Government of 800 million strong people. Do you mean to say that you are so weak that such things easily happen because of a foreign hand? What are you doing to identify and deal with this foreign hand? Would you please give an assurance here and now—I have full confidence in the young Minister-that you would take a policy decision that you would not ever negotiate with terrorists whether a Minister is kidnapped or a Minister's, son is kidnapped or a Member of Parliament is kidnapped and kept as hostage. Would you give an assurance that you would never negotiate on their terms? If it is on your terms, it is a different story. This is a serious thing. Even in the case of Hazratbal, such a thing had happened. Incidentally, I would like to have a White Paper on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Would you please put the question?

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, I am putting the question. Would the hon. Minister give a commitment that the Government would not negotiate with terrorists or militants? Would he give an assurance that the honour of the country would be maintained and the militants given a clear-cut signal that here is a strong Government which would live up to its reputation? Would you please do that? Would you assure that you would never compromise?

उपसभापतिः जितना लम्बा सवाल है, नाट नेसेसरी कि जवाब भी उसी लम्बान का हो क्योंकि आपने बड़े विस्तार से बताया है।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: It is a question of the honour of the country, Madam. I am absolutely worked up. What are we doing as a Government? *(Interruptions)*

SHRI DEPUTY CHAIRMAN: I understand the seriousness of your question, but I am only telling the Minister that he should answer it pointedly. That is all the matter.

SHRI RAJESH PILOT: Madam, I share the sentiments of the hon. Member. I assure the hon. Member that at no stage the honour of the country would be jeopardised by negotiating with terrorists or militants or any of their organisations. But the situation in Kashmir is such that the fear of the gun is still there. I have seen. I have talked to the people. They have still the fear of the gun. When we go and talk to these people, the next day the terrorists threaten them saying 'Why did you talk to a Government official or a politician?.' This sort of thing is there. However, the security forces are facing this challenge. They are fighting the terrorists. They are trying to do their best. I can assure the hon. Member that at no stage the honour of the country would be compromised.

After our Government came to power in 1991, we did not negotiate with any militant or any terrorist where the national interests were concerned. The national interests have always been kept above everything. We have been fighting militancy. You can see the record of the Government since 1991. The number of attacks on militants has increased. Militancy has decreased. But sometimes, some odd instances take place here and there, like the one at Lal Chowk, the one at Sopore, etc. These are instances where the terrorists try to hinder our efforts, but we are meeting this challenge. I did not get the second part of the question of the hon. Member.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Would you assure that you would not hesitate even to storm the places of worship to whichever religion they may belong if such places of worship are used by militants?

SHRI RAJESH PILOT: I hope the hon. Member would agree that one has to see the situation where the national feelings are concerned. We have to keep in mind the national interests. As a Government, we have to consider the situation, assess the situation. Even in the case of Hazratbal, we have nothing to hide. The hon. Member asked for a White Paper on this. We arc ready to explain everything to the House. We have nothing to hide. The hon. Home Minister has said in one of the Houses that everthing is clear. We know what the State Government has done. We are ready to place the facts before the House. There is nothing which we want to keep away from the House. As I said, we have to take into account the various factors while assessing a situation and then act on those lines. This we have got to bear in mind.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Would you place a White Peper?

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: I would like to know whether, in order to prevent such attacks in future, any rocket device or such other sophisticated equipment has been installed near the T.V. station to detect any impending rocket or missile attack.

SHRI RAJESH PILOT: As I said earlier, last week, there was a meeting with the scientists and others. We could evolve a device which people from outside cannot see. Whenever they fire, they fire either at a building or at a pinpointed individual or room. That was the idea. That has been done. I am told that a screen has been erected wherever you cannot see inside of a particular building.

The hon. Member has asked whether there could be any anti-rocket device. This fact I may not be able to answer at the moment without talking to the concerned expert people, but the Government is concerned because it has been very frequent that the targets have either been the Secetariat or Doordarshan and All India Radio kendras when they are functioning. Frequently these two places have been the targets. The Government is concerned about it. We are certainly working on it to avoid recurrence of such attacks in future.

SHRI G.G. SWELL: Madam, this incident is another proof that violence in Kashmir has not abated, on the other hand, it has intensified. I would like to know from the Minister, what has happened to those militants who came out from the Hazrat Bal shrine, including those foreigners from the Pakistan-occupied Kashmir, where they are now, what steps have been taken about them.

My second question is whether you have seen the reports in the newspapers that during her visit to Turkey, the Pakistan Prime Minister Benazir Bhutto has been assured that both Turkey and Iran will use their good offices for settlement of the Kashmir issue in favour of Pakistan.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The second part of the question does not come under his Ministry, not associated with this question. You put a separate question for the External Affairs

Ministry. I do not think the Minister is expected to answer that. But he can answer the first part of your question.

SHRI G. G. SWELL: It is a complex issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know we can put a complex question.

SHRI RAJESH PILOT: The hon. Member in his first part of the question has asked about the Hazrat Bal incident. As the House is aware, the State Government has given a very clear statement that after surrender the law will take its course. So, they were handed over to the court, there is a process going on.

About the number of released militants, I think if the hon. Member puts a separate question I will be able to give a complete picture. At the moment I won't be able to tell how many have been released, on what date and how they were released, but the Government policy is very clear that after their surrender the State law will take its own course. So, the process is being followed.

Sanctuaries and National Parks in the Country

*183. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:
Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what are the details of the sanctuaries and national parks that have come up in the country during the last three years, year-wise;

(b) what is the number of tribal belts (showing the number of persons) affected as a consequences thereof; and

(c) what are the alternative rehabilitation arrangements made by Government of the displaced tribals to earn their livelihood?

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Prakash Malaviya.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The number of National Parks and Sanctuaries that have come up in last three years are as follows:

Year	National parks	Sanctuaries
1991	3	4
1992	2	5
1993	—	—

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per the Wild Life (Protection) Act, 1972, as amended in 1991, a sanctuary or a National Park can be finally declared as one, only when all the claims and rights of the people over the land comprising the protected area are finally settled. These rights are determined by a Collector appointed by the State Government for the purpose, following the procedure as laid down in Section 19 to 25 of the Act. Every care is taken to ensure that the people having rights over such areas are not adversely affected and they are duly compensated in case their rights are acquired. The total number of tribals affected as a consequence of the constitution of National parks and Sanctuaries is difficult to ascertain as in addition to direct impact of protected areas on included population the impact extend to peripheral villages also and the limit of such fringe dwellers vary from area to area depending on socioeconomic and cultural aspect of local population as well as the topographic and esaphic condition of the localities.

The Central Government, on request, gives assistance to the State Governments whenever a tribal population is to be rehabilitated outside a protected area as a consequence of the constitution of a National Park of Sanctuary under the 'Beneficiary-oriented Scheme', the Scheme of the Development of 'National Parks and Sanctuaries', 'Project Tiger' and the 'Project Elephant'. A Scheme of 'Eco-development in and around Protected Areas' is also being